



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शक्रवार, 19 दिसम्बर, 2003/28 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 19 दिसम्बर, 2003

संख्या वि०स०-गवरनमेंट बिल/1-110/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2003

(2003 का विधेयक सख्यांक 21) जो आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम । 2003 है ।

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धारा 4 का “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन ।

(क) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(12) किसी सम्पदा या सम्पदाओं के समूह की “शुद्ध परिसम्पत्तियों” से ऐसी सम्पदा या सम्पदाओं के समूह की प्राक्कलित औसत वार्षिक अधिशेष उपज अभिप्रेत है जो यथा अभिनिश्चित या प्राक्कलित खेती के मामूली खर्चों को घटाने के पश्चात् शेष रह जाती है ;

स्पष्टीकरण.—खेती के मामूली खर्चों के अन्तर्गत ऐसे संदाय, यदि कोई हों, अभिप्रेत है, जिन्हें भू-स्वामी, चाहे वस्तु रूप में या नकद रूप में या पूर्णतया या भागतः निम्नलिखित की बाबत प्रथागत वहन करता है,—

- (i) पानी की दरें;
- (ii) सिंचाई के साधनों का रख-रखाव;
- (iii) तटबन्धों का रख-रखाव;
- (iv) बीज का प्रदाय;
- (v) खाद का प्रदाय;
- (vi) कृषि (खेती) के लिए उन्नत औजार;
- (vii) चारे के सम्बन्ध में रियायतें;
- (viii) परती भूमि या खराब फसलों के लिए दी गई विशेष कटौतियां;
- (ix) भाटक (रेंट) के संग्रहण में लागत ;
- (x) भाटक (रेंट) के संग्रहण में आई कमी को पूरा करने के लिए दी गई छूट ;
- (xi) खेती के प्रयोजन के लिए अभिधारियों को नकद और ब्याज मुक्त अग्रिमों की बाबत संदेय ब्याज प्रभार ; और
- (xii) शिल्पकारों या छोटे कामगारों को संदत्त की गई मजदूरी या प्रथागत देय, जिनके उत्पादों या श्रम का उपयोग कृषि प्रयोजनों या फसल की कटाई के लिए किया जाता है और ऐसा भाग (हिस्सा) जो एक अभिधारी द्वारा रखा

जा सकेगा यदि भूमि, सम्पदा या सम्पदाओं के समूह में वस्तुतः प्रचलित सामान्य दर पर, चाहे नकद या वस्तु रूप में, भाटक (रेंट) संदत्त करने वाले अधिभोगी अभिधारी को दी जाती है; ” ; और

(ख) खण्ड 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(17) “राजस्व अधिकारी” का, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध में, तात्पर्य ऐसे राजस्व अधिकारी से है जिसको उस उपबन्ध के अधीन राजस्व अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार प्राप्त हो ;” ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) राजस्व अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) फाईनैन्शियल कमिशनर ;
- (ख) कमिशनर ;
- (ग) कलक्टर ;
- (घ) एसिस्टेंट कलक्टर प्रथम ग्रेड ; और
- (ङ) एसिस्टेंट कलक्टर द्वितीय ग्रेड ।” ; और

(ख) उप-धारा (3) में चिन्ह और शब्दों “एक्स्ट्रा एसिस्टेंट कमिशनर” का लोप किया जायेगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) यदि किसी मामले (मुकद्दमे) में, जिसमें कमिशनर या कलक्टर ने अभिलेख मंगाया है, की यह राय है कि उसमें की गई कार्यवाहियों को या किए गए आदेश को उपांतरित या उलट दिया जाना चाहिए, तो वह उस पर अपनी राय सहित मामले को फाईनैन्शियल कमिशनर के पास उसके द्वारा आदेश के लिए भेज देगा ।

(4) फाईनैन्शियल कमिशनर किसी भी मामले में, जिसे उसने उप-धारा (1) के अधीन मंगाया हो या जो उसे उप-धारा (3) के अधीन भेजा गया हो, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु वह अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को उलटने या उपांतरित करने वाला तथा प्राईवेट व्यक्तियों के मध्य अधिकार के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, इस धारा के अधीन पारित नहीं करेगा ।” ।

5. मूल अधिनियम की धारा 23-क और 23-ख का लोप किया जाएगा। धारा 23-क और 23-ख का लोप।
6. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) में "और राजस्व न्यायालय" शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 25 का संशोधन।
7. मूल अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा। धारा 28 का संशोधन।
8. मूल अधिनियम की धारा 33 में उप-धारा (4), (5), (6), (7) और (8) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- धारा 33 का संशोधन।

"(4) तैयार किए जाने वाले या विशेष रूप से पुनरीक्षित किए जाने वाले अधिकार अभिलेख विहित रीति में बनाए जाएंगे।

(5) जब किसी जिले या उसके किसी भाग के अधिकार अभिलेख का विशेष पुनरीक्षण करने की तथा भू-राजस्व के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही हो, तो अधिकार अभिलेख तैयार करने और उन्हें बनाए रखने का कर्तव्य बन्दोबस्त कलक्टर को अन्तरित किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन कलक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(6) जब अधिकार अभिलेख तैयार कर लिए जाएं या विशेषतया पुनरीक्षित कर लिए जाएं तो उन्हें सम्पदा के भीतर विहित रीति में प्रकाशित किया जाएगा।

(7) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार अधिकार अभिलेख में किसी भी प्रविष्टि के विरुद्ध तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप प्रस्तुत करता है तो उनका विनिश्चय राजस्व अधिकारी द्वारा एक मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और राजस्व अधिकारी के आदेशों को, यदि कोई हों, सम्पदा के अधिकार अभिलेख में कार्यान्वित (प्रभावी) करने के पश्चात्, अधिकार अभिलेख अन्ततः सम्पदा के भीतर विहित रीति में प्रकाशित किए जाएंगे।

(8) उप-धारा (7) के अधीन अधिकार अभिलेख के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् बन्दोबस्त पटवारी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी धृति के नए मापे गए खसरा नम्बरों की जमाबन्दी और ततीमा की एक प्रति का निःशुल्क प्रदाय करेगा।

(9) जैसे ही किसी सम्पदा के अधिकार अभिलेख को तैयार करने या उसका विशेष पुनरीक्षण करने तथा भू-राजस्व के निर्धारण का कार्य पूरा हो जाता है तो, यथास्थिति, अधिकार अभिलेख को तैयार करने या उसका पुनरीक्षण करने के कार्य को बन्द किए जाने की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की जाएगी।"

9. मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- धारा 37 का प्रति-स्थापन।

"37. विवाद का अवधारण.—(1) यदि किसी अभिलेख को बनाने, पुनरीक्षण करने या तैयार करने के दौरान या इस अध्याय के अधीन किसी जांच के दौरान किसी ऐसे विषय के बारे में, जिसकी अभिलेख या इस्तकाल के रजिस्टर

में कोई प्रविष्टि की जानी हो, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राजस्व अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितवद्ध पक्षकार के आवेदन पर, परन्तु ठीक आगामी धारा के उपबन्धों के अधीन, तथा ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, उस विषय की बाबत प्रविष्टि का अवधारण करेगा।

(2) यदि ऐसे किसी विवाद में राजस्व अधिकारी का यह समाधान न हो सके कि विवाद से सम्बन्धित सम्पत्ति किस पक्षकार के कब्जे में है तो वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित ग्राम पंचायत के माध्यम से या फाईनैन्शियल कमिश्नर द्वारा विहित अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से या संक्षिप्त जांच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि कौन सा व्यक्ति सम्पत्ति का सही हकदार है और आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि उस व्यक्ति को उस सम्पत्ति का कब्जा दे दिया जाए और उस आदेश के अनुसार अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी जाए।

(1994 का 4)

(3) उप-धारा (2) के अधीन राजस्व अधिकारी का निदेश किसी ऐसी डिक्री या आदेश के अधीन होगा जो सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् पारित किया जा सकेगा।”।

धारा 46
का प्रति-
स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“46. अभिलेख में की गई प्रविष्टि द्वारा पीड़ित (व्यथित) व्यक्तियों का घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद.—यदि कोई व्यक्ति अधिकार अभिलेख या कालिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि द्वारा मिले हुए किसी अधिकार के सम्बन्ध में स्वयं को पीड़ित (व्यथित) समझता है तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय-VI के अधीन अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।”।

(1963 का 47)

धारा 50
का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 50 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) सम्पदा या सम्पदा समूहों, जिसमें सम्बन्धित भूमि स्थित है, की शुद्ध परिसम्पत्तियों का औसत धन मूल्य ; या ”।

धारा 51
का प्रति-
स्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 51 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“51. निर्धारण की सीमा.—यदि भू-राजस्व नियत वार्षिक प्रभार के रूप में निर्धारित किया गया है तो उसकी राशि, और यदि इसे विहित दर के रूप में निर्धारित किया गया है तो औसत राशि जो, राज्य सरकार द्वारा लिखित में अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार प्रतिवर्ष उद्ग्राह्य होगी, किसी निर्धारण मण्डल की दशा में ऐसे निर्धारण मण्डल की शुद्ध परिसम्पत्तियों के प्राक्कलित धन मूल्य के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी या निर्धारण मण्डल या उसके भाग में

गैर-कृषि (अकृषि) उपयोग के लिए रखी भूमि के स्थलों के प्रवर्ग और श्रेणी पर विशेष निर्धारण की दशा में,—

- (क) प्राक्कलित औसत शुद्ध भाटक मूल्य के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी ;
या
- (ख) औसत बाजार मूल्य के दो से चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;
या
- (ग) खाली पड़े हुए और उपयोग में नहीं स्थलों की दशा में औसत बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।”

13. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

धारा 54
का संशोधन ।

- (क) उप-धारा (1) में, “राज्य शासन” शब्दों के पश्चात् “उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,” शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

- (ख) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारण मण्डल, जो ऐसे क्षेत्र का भाग है जिसके सम्बन्ध में धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, पर उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन अधिरोपित भू-राजस्व के आपतन की औसत दर अन्तिम पूर्व निर्धारण पर अधिरोपित भू-राजस्व के आपतन की दर के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी :

परन्तु किसी सम्पदा पर अधिरोपित निर्धारण के आपतन की दर, उस सम्पदा पर अन्तिम पूर्ण निर्धारण के आपतन की दर के तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी ।

- (4) उप-धारा (3) के उपबन्ध उस भूमि की दशा में लागू नहीं होंगे,—

- (क) जिसका पूर्व में भू-राजस्व के लिए निर्धारण नहीं हुआ है ; या
- (ख) जो फलोत्पादक बगीचे (फलोद्यान) के अन्तर्गत आती है ; या
- (ग) जो चाय बागान के अन्तर्गत आती है ; या
- (घ) जिसमें अन्तिम पूर्ववर्ती निर्धारण के समय उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन पारित आदेश की तारीख के पश्चात् कुहलें या अन्य कृत्रिम सिंचाई प्रयोग में लाई गई है ; या
- (ङ) जिसकी बाबत अन्तिम पूर्ववर्ती निर्धारण धारा 63 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन किया गया था ; या
- (च) जिसे अधिसूचना द्वारा नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित किया गया है :

परन्तु यह कि उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए, भू-राजस्व के आपतन में बढौतरी के परिकलन के प्रयोजन के लिए, ऐसी समस्त भूमि परिकलन से अपवर्जित की जाएगी :

परन्तु यह कि नगर निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर आने वाले समस्त क्षेत्र, नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित किए जाएंगे और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य उपयुक्त क्षेत्र को नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित कर सकेगी ।” ।

धारा 57
का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) में,—

- (क) “बीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “चालीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ; और
(ख) खण्ड (ii) के परन्तुक में “उप-धारा (3)” शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर “उप-धारा (4)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 64
का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) किसी सम्पदा या सम्पदा समूह की शुद्ध परिसम्पत्तियों के धन मूल्य का प्राक्कलन करने का तरीका ;” ; और

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(ङ) वह रीति जिसके अनुसार धारा 54 की उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ भू-राजस्व के आपतन की दर का परिकलन किया जाना है ।” ।

धारा 107
का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (3) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में, शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने की व्यवस्था करने तथा साथ ही राजस्व मामलों में दीर्घकालिक मुकद्दमेबाजी रोकने के लिए, वर्ष 2000 में संशोधन कर राजस्व न्यायालयों की संकल्पना की गई थी। वांछित उद्देश्य पूरे नहीं हो सके क्योंकि अधिनियम को पुनः संशोधित करके हक के प्रश्न से सम्बन्धित मामलों में विनिश्चय करने के लिए राजस्व न्यायालयों को निर्बन्धित कर दिया गया। इसलिए राजस्व न्यायालयों की संकल्पना को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है। राजस्व अधिकारियों की केवल पांच श्रेणियां हैं अर्थात् वित्तायुक्त, आयुक्त, कलक्टर, एसिस्टेंट कलक्टर प्रथम ग्रेड और एसिस्टेंट कलक्टर द्वितीय ग्रेड तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 में जोड़ी गई शेष श्रेणियां अनावश्यक हैं। इस प्रकार "एक्सट्रा एसिस्टेंट कमिशनर" का पद भी अविद्यमान पद है। इसलिए उपरोक्त अधिनियम में और संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

धारा 17 के विद्यमान उपबन्ध अस्पष्टता पैदा करते हैं, क्योंकि आयुक्त और वित्तायुक्त दोनों में पुनरीक्षण की शक्तियां निहित हैं। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए यह भी विनिश्चय किया गया है कि वित्तायुक्त के राजस्व मामलों में एक मात्र सर्वोच्च अपील प्राधिकारी होने के कारण पुनरीक्षण की शक्तियां उसमें ही निहित होंगी। धारा 28 में राजस्व अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने का उपबन्ध है परन्तु तहसीलदार/नायब-तहसीलदार काडर से प्रोन्नत से भिन्न राजस्व अधिकारियों को अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि वे उप-धारा (4) के अधीन अधिरोपित शर्तें परिपूर्ण नहीं कर लेते। परिणामस्वरूप जनता राजस्व मामलों में प्रतिरोध प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस कर रही है। इसलिए इस अस्पष्टता को दूर करने तथा उपबन्धों को स्पष्ट बनाने का विनिश्चय किया गया है।

धारा 33 की उप-धारा (5) यह उपबन्धित करती है कि बन्दोबस्त अधिकारी अधिनियम के अध्याय-IV के अधीन कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करेंगे जबकि अधिनियम के विभिन्न अध्यायों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त धारा 33 की उप-धारा (6) बन्दोबस्त के पूर्ण होने पर प्रत्येक अधिकार धारक को पुरानी और नई मुसाबी की प्रति सहित, किसान पास बुक की प्रति का प्रदाय करने का भी उपबन्ध करती है। इस उपबन्ध में इनकी अपनी व्यावहारिक विवक्षाएं अन्तर्निहित हैं क्योंकि अधिक कार्य होने के कारण सम्पदा के प्रत्येक अधिकार धारक को पुरानी और नई मुसाबी की प्रति प्रदान करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त स्थाई अभिलेख को अन्तिम रूप देने के पश्चात् इसे फोल्ड स्टाफ के पास रखना इसके साथ छेड़छाड़ करने और इसे नष्ट करने के लिए बढ़ावा देना है। धारा 33 की उप-धारा (7) का परन्तु केवल उप-धारा (6) का प्रत्युत्पादन है। इसलिए इन त्रुटियों को दूर करने के लिए उपरोक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

शुद्ध परिसम्पत्तियों का सिद्धांत जो भू-राजस्व के निर्धारण के लिए अनुमानित औसत वार्षिक अतिशेष उपज से खेती के साधारण खर्चों को घटा कर संगणना की व्यवस्था करता है वैज्ञानिक विधि पर आधारित था। इसे भू-राजस्व के निर्धारण की प्रक्रिया के सरलीकरण के बहाने समाप्त नहीं करना चाहिए। विद्यमान उपबन्धों के अनुसार किसी सम्पदा में, केवल कृषि भूमि ही भू-राजस्व के निर्धारण के अध्याधीन है और शेष भूमि जैसे कि प्राइवेट वन, प्राइवेट भूमि पर भवन, घासनियां, घराट या कोई अन्य गैर मुसकिन भूमि निर्धारण के दायरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त, भू-राजस्व कर नहीं है और इसे भूमि से प्राप्त अधिशेष उपज को ध्यान में रख कर संगणित

किया जाना चाहिए। उपरोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार निर्धारण के लिए नियत सीमा राज्य के गरीब किसानों के लिए अहितकर प्रतीत होती है जहां भू-स्वामियों की अधिकतर संख्या छोटे और सीमान्त भू-स्वामियों की है। इसलिए भू-राजस्व के निर्धारण से सम्बन्धित पूर्वतर उपबन्धों को उनकी मूल स्थिति में प्रत्या-वर्तित किए जाने और अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों में यथोचित संशोधन करने का भी विनिश्चय किया गया है। इन्हीं कारणों से उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

बृज बिहारी लाल बटेल,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : , 2003

वित्तीय जापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2003.

**THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT)
BILL, 2003**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953
(Act No. 6 of 1954).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2003.

Short title.

1954)

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

Amendment of section 4.

(a) after clause (11), the following clause shall be added, namely:—

“(12). “net-assets” of an estate or group of estates means the estimated average annual surplus produce of such estate or group of estates remaining after deduction of the ordinary expenses of cultivation as ascertained or estimated ;

Explanation.—Ordinary expenses of cultivation include payments, if any, which the land-owner customarily bears whether in kind or in cash either in whole or in part in respect of,—

- (i) water rates ;
- (ii) maintenance of means of irrigation ;
- (iii) maintenance of embankments ;
- (iv) supply of seed ;
- (v) supply of manure ;
- (vi) improved implements of husbandry ;
- (vii) concessions with regard to fodder ;
- (viii) special abatements made for fallows or bad harvests ;
- (ix) cost of collection of rent ;
- (x) allowance for shortage in collection of rent ;
- (xi) interest charges payable in respect of advances made in cash, free of interest, to tenants for the purpose of cultivation ; and

(xii) wages or customary dues paid to artisans or menials whose products or labour are utilised for the purposes of cultivation and harvesting, and the share that would be retainable by a tenant if the land were let to a non-occupancy tenant paying rent, whether in cash or in kind, at the normal rate actually prevalent in the estate or group of estates ;"; and

(b) for clause (17), the following shall be substituted, namely:—

“(17) “Revenue Officer” in any provision of this Act, means a Revenue Officer having authority under this Act to discharge the functions of a Revenue Officer under that provision;”.

Amend-
ment of
section 7.

3. In section 7 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) There shall be the following classes of Revenue Officers, namely:—

- (a) the Financial Commissioner ;
- (b) the Commissioner ;
- (c) the Collector ;
- (d) the Assistant Collector of the first grade ; and
- (e) the Assistant Collector of the second grade.” ; and

(b) in sub-section (3), the sign and words “, Extra-Assistant Commissioner” shall be deleted.

mend-
ment of
section 17.

4. In section 17 of the principal Act, for sub-sections (3) and (4), the following shall be substituted, namely:—

“(3) If in any case in which a Commissioner or Collector has called for a record, is of the opinion that the proceedings taken or order made should be modified or reversed, he shall report the case with his opinion thereon for the orders of the Financial Commissioner.

(4) The Financial Commissioner may in any case called for by himself under sub-section (1) or reported to him under sub-section (3) pass such order as he thinks fit :

Provided that he shall not under this section pass an order reversing or modifying any proceeding or order of a subordinate Revenue Officer and effecting any question of right between private persons without giving those persons an opportunity of being heard.”.

Deletion of
sections 23-
A and 23-B.

5. Sections 23-A and 23-B of the principal Act, shall be deleted.

6. In section 25 of the principal Act, in sub-section (1), the words "and Revenue Courts" shall be deleted.

Amendment of section 25.

7. In section 28 of the principal Act, sub-section (4) shall be deleted.

Amendment of section 28.

8. In section 33 of the principal Act, for sub-sections (4), (5), (6), (7) and (8), the following shall be substituted, namely:—

Amendment of section 33.

"(4) The record-of-rights to be made or specially revised shall be done in the manner prescribed.

(5) When a District or a part thereof, for making of special revision of record-of-rights and assessment of land revenue, is in process, the duty of preparing and maintaining of record-of-rights shall be transferred to the Settlement Collector who shall exercise all the powers of the Collector under this Act.

(6) When the record-of-rights are made or specially revised, the same shall be published within the estate in the manner prescribed.

(7) If any party interested files objections, against any entry in the record-of-rights within a period of 30 days, the same shall be decided by the Revenue Officer within a period of one month and after giving effect to the orders of the Revenue Officer, if any, in the record-of-rights of the estate, the record-of-rights shall be finally published within the estate in the manner prescribed.

(8) After the final publication of the record-of-rights under sub-section (7), the settlement patwari shall supply to every person a copy of measurement Jamabandi and Tatima of newly measured Khasra numbers of his holding free of cost.

(9) As soon as the work of making or special revision of record-of-rights and assessment of land revenue of an estate is over, a notification shall be issued declaring the making or revision of record-of-rights, as the case may be, to be closed."

9. For section 37 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 37.

"37. *Determination of dispute.*—(1) If during the making, revision or preparation of any record or in the course of any enquiry under this Chapter a dispute arises as to any matter of which an entry is to be made in a record or in a register of mutations, a Revenue Officer may of his own motion or on the application of any party interested, but subject to the provisions of the next following section, and after such inquiry as he thinks fit, determine the entry to be made as to that matter.

(2) If in any such dispute the Revenue Officer is unable to satisfy himself as to which of the parties thereto is in possession of any property to which the dispute relates, he shall ascertain

through the Gram Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 or any other agency so prescribed by the Financial Commissioner or by summary inquiry who is the person best entitled to the property, and shall by order direct that, that person be put in possession thereof, and that an entry in accordance with that order be made in the record or register.

(4 of 1994)

- (3) A direction of a Revenue Officer under sub-section (2) shall be subject to any decree or order which may be subsequently passed by any Court of competent jurisdiction.”.

10. For section 46 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“46. *Suit for declaratory decree by persons aggrieved by an entry in a record.*—If any person considers himself aggrieved as to any right of which he is in possession by an entry in a record-of-rights or in a periodical record, he may institute a suit for a declaration of his right under Chapter VI of the Specific Relief Act, 1963.”.

(47 of 1963)

11. In section 50 of the principal Act, for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

“(a) the average money value of the net assets of the estate or group of estates in which the land concerned is situated ; or”.

12. For section 51 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“51. *Limit of assessment.*—If the land-revenue is assessed as a fixed annual charge the amount thereof, and, if it is assessed in the form of prescribed rate, the average amount which, according to an estimate in writing approved by the State Government will be leviable annually shall not, in the case of any assessment circle exceed one-fourth of the estimated money value of the net assets of such assessment circle or in the case of special assessment on a category and class of sites of land put to non-agricultural use in an assessment circle or part thereof—

(a) exceed one-fourth of the estimated average net letting value ;
or

(b) exceed two to four percent of average market value ; or

(c) in the case of sites lying vacant and out of use, exceed one percent of average market value :

Provided that nothing contained in this section shall affect any assessment in force at the time of the commencement of this Act.”.

Substitution of section 46.

Amendment of section 50.

Substitution of section 51.

13. In section 54 of the principal Act,—

Amend-
ment of
section 54.

(a) in sub-section (1), after the words “as it may deem fit”, the sign, words, brackets and figures “,subject to the provisions of sub-sections (3) and (4)” shall be inserted ; and

(b) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(3). Subject to the provisions of sub-section (4), the average rate of incidence on the cultivated area of the land-revenue imposed under the provisions of sub-section (1) on any assessment circle forming part of any area in respect of which a notification has been issued under sub-section (2) of section 52 shall not exceed the rate of incidence of the land revenue imposed at the last previous assessment by more than one-third :

Provided that the rate of incidence of the assessment imposed on any estate shall not exceed the rate of incidence of the last previous assessment on that estate by more than three-fourth.

(4) The provisions of sub-section (3) shall not be applicable in the case of land,—

(a) which has not previously been assessed to land revenue ;
or

(b) which is under fruit bearing orchards ; or

(c) which is under tea plantation ; or

(d) in which kuhls or other artificial irrigation has been introduced after the date of the orders passed under the provisions of sub-section (1) at the last previous assessment ; or

(e) whose last previous assessment was made under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 63 ; or

(f) which has been declared by notification to be urban assessment circle :

Provided that for the purpose of calculating the increase in the incidence of the land revenue for the purpose of sub-section (3), all such land shall be excluded from calculation :

Provided further that all areas falling within the limits of a Municipal Corporation, Municipal Council, or Nagar Panchayat shall be declared as urban assessment circles and the State Government may by notification declare any other suitable area to be an urban assessment circle.”

Amend-
ment of
section 57.

14. In section 57 of the principal Act, in sub-section (2),—

- (a) for the words “twenty years”, the words “forty years” shall be substituted ; and
- (b) in proviso, in clause (ii), for the word, bracket and figure “sub-section (3)”, the word, bracket and figure “sub-section (4)” shall be substituted.

Amend-
ment of
section 64.

15. In section 64 of the principal Act,—

- (a) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

“(a) the method by which the estimate of the money value of the net assets of an estate or group of estates shall be made ;” ; and

- (b) after clause (d), the following clause shall be added namely:—

“(e) the manner in which the rate of incidence of the land-revenue is to be calculated for the purpose of sub-section (3) of section 54.”.

Amendment
of section
107.

16. In section 7 of the principal Act, sub-section (3) shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The concept of Revenue Courts was introduced in the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954) by amending the Act *ibid* in the year 2000 to provide for speedy and cheap justice and also to prevent the protracted litigation in revenue matters. The desired objectives remained unfulfilled for the reasons that the Act was again amended restricting the Revenue Courts from deciding the matters pertaining to question of title. Thus it has been decided to do away with the concept of Revenue Courts. There are only five classes of Revenue Officers *i. e.* Financial Commissioner, Commissioner, Collector, Assistant Collector First Grade, Assistant Collector Second Grade and rest of the categories added in section 7 of the Act *ibid* are superfluous. Similarly, the "Extra-Assistant Commissioner" is a non existant post. Hence, it has further been decided to carry out necessary amendment in the Act *ibid*.

The existing provisions of section 17 creates an ambiguity as both Commissioner and Financial Commissioner are vested with the revisionary powers. In order to remove this ambiguity, it has also been decided that only Financial Commissioner should be vested with such powers, being the highest appellate authority in revenue matters. Section 28 provides for the conferment of powers to Revenue Officers but the Revenue Officers, other than promoted from Tehsildar/Naib Tehsildar cadre, cannot be conferred with such powers under the Act unless they fulfill the conditions imposed under sub-section (4). Resultantly, the general public is facing great difficulties to get redressal in revenue matters. Hence, it has been decided to remove this ambiguity and to make the provisions clear.

Sub-section (5) of section 33 provides that the Settlement Officers shall exercise the powers of Collector under Chapter IV of the Act, whereas, the Settlement Officer exercises such powers under different Chapters of the Act. Further sub-section (6) of section 33 provides for supply of a copy of Kisan Pass Book alongwith a copy of old and new "Mussavi" on completion of settlement operations to each right holder. This provision has its inherent practical implications as it is not possible to supply the copy of old and new "Mussavi" to each right holders of an estate being a voluminous work. Moreover, to keep the standing record with field staff after finalisation may lead to tempering and destruction. The proviso to sub-section (7) of section 33 is mere reproduction of sub-section (6). Thus in order to remove these defects, it has been decided to make suitable amendments in the Act *ibid*.

The theory of net assets which provides for calculation by deducting the ordinary expenses of cultivation from the estimated average annual surplus produce for the assessment of land revenue was based on scientific method. It should not be done away with under the guise of simplification of procedure for assessment of land revenue. As per existing provisions only agricultural land in an estate is subject to assessment of land revenue and the rest of land *i.e.* private forests, building on private land, ghasnies, gharats or any other gair mumkin land is out of the perview of assessment. Moreover, land revenue is not a tax and it should be calculated keeping in view the surplus produce derived from the land. As per existing provisions of the Act *ibid*, the limit of assessment fixed seems to be detrimental to the interest of poor farmers of the State where the majority of the land owners are small and marginal landowners. Hence, it has also been decided to restore the earlier provisions relating to assessment of land revenue to their original position and to amend the relevant provisions of the Act *ibid* suitably. This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

BRIJ BIHARI LAL BUTAIL,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Dated ::....., 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM**-NIL-**

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**-NIL-**